

विचार बिन्दु

वसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं। -हरिशंकर परसाई

चुनावी लोकतंत्र या स्थायी चुनावी मोड़?

भा रत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अब यह वाक्य कुछ वैसा ही हो गया है जैसे शादी-ब्याह के कार्ड में "धेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण तुम्हें बुलाने को/ हे मानस के राजहंस, भूल न जाना आने को" -छपवाना जरूरी है, भले ही निमंत्रण पाने वाला राजहंस तो क्या कोआ भी न हो! ऐसा ही कुछ हाल लोकतंत्र का भी है। पहले लोकतंत्र का मतलब शासन, नीति और जवाबदेही होता था अब उसका अर्थ बदल गया है। अब इसका एक ही अर्थिप्रय है-अगला चुनावी कब है?

2024 के आम चुनावों के बाद देश को थांडी राहत मिलनी चाहिए थी-जैसे शादी की लम्बी भागदौड़ के बाद घर वाले चैन की सांस लेते हैं। अपने यहां तो ब्याह संपन्न करवा लेने के बाद गंगा जी नहाने तक की परंपरा रही है। लेकिन जहां तक भारत में लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप की बात है, यहाँ तो बारात विदा होते ही अगली बारात की तैयारी शुरू होने लगी है। मुझे अनायास रमेश कच्छी की एक कहानी याद आ रही है। कहानी का शीर्षक है - अगले मुहर्रम की तैयारी। तलाश करके इस कहानी को पढ़ें। देश में लोकतंत्र का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। चुनाव, चाहे वह कोई-सा भी हो। लोकसभा का, राज्य सभा का, विधान सभा का, पंचायत का, यहां तक कि वाई का भी। चुनाव नहीं तो उप चुनाव ही सही। और चुनाव नहीं तो दूसरे दलों में तोड़ फोड़ का कार्यक्रम भी चलेगा। आखिर वह भी चुनाव का ही हिस्सा है। देश एक स्थायी चुनावी मेले में तब्दील हो गया है, जहाँ मंच कभी खाली नहीं रहता, सिर्फ पोस्टर बदलते रहते हैं। जैसे सिनेमाघर कभी खाली नहीं रहता, बस फिल्म के पोस्टर बदलते हैं। जैसे कुछ दुकानों पर स्थायी सेल चलती रहती है और कुछ मैदानों में स्थायी रूप से मेले लगते रहते हैं, वैसे ही हमारे देश में बारहों महीने चुनाव चलते रहते हैं। पहले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था-भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब पढ़ाया जाना चाहिए- भारत एक चुनाव प्रधान देश है। हमारे नेताओं की तारीफ को जानी चाहिए, कि और सारे आलतू-फालतू कामों को स्थगित रख कर वे पूरी ईमानदारी से चुनाव में जुटे रहते हैं। इसके लिए उन्हें अटारह-अटारह घण्टे काम करना पड़े तो भी वे अपने कर्तव्य चुप से हटते नहीं हैं।

ऐसा नहीं है कि हमारे नेता और कोई काम नहीं करते। करते हैं। वे सोचने का काम करते हैं। वे अहंशिय यह सोचते रहते हैं कि अगले चुनाव के लिए कौन-सा नया वादा ठीक रहेगा। यह भी कि चुनाव हो जाने के बाद उस वादे को विस्मृत किस कौशल से करना है, या उसके पूरा न होने की क्या सफाई देनी है। वैसे तो इस मामले में जनता भी उनकी पूरी मदद करती है। वह खुद ही उनसे नहीं पूछती कि हजूर, आप पिछले वादे का क्या हुआ? मान लीजिए कि आजकल हर घोषणा के पीछे एक अदृश्य नोट लिखा होता है-शर्तें लायू: यह योजना अगले चुनाव तक वैध है। बजट अब आर्थिक दस्तावेज कम, चुनावी पैकेज अधिक लगते हैं। घोषणाएँ इस अंदाज में होती हैं जैसे सरकार नहीं, कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फेस्टिव सेल चला रहा हो-अभी लें, वोट के साथ कैशबैक पाएँ। नेतागण ये वादे अत्यधिक उदारता के साथ करते हैं। तुम्हारे यहां चुनाव हो रहा है। ठीका हमारी सरकार बन गई तो हरेक को इतनी रकम या यह वस्तु या यह सुविधा मुफ्त में देंगे। दो बातें हैं। एक तो यह कि जो भी देने का वादा कर रहे हैं वह कौन अपनी जेब से पूरा करना है! मियाँ की जुली मियाँ के सर वाला मामला होना है। लेकिन इसकी भी कोई

असल में मीडिया ने इस पूरे परिदृश्य को एक नया आयाम दे दिया है। खबर अब सूचना नहीं, कंटेंट है-और कंटेंट वही अच्छा है, जो ज्यादा बिके। एंकर अब प्रश्न पूछने के बजाय निर्णय सुनाने लगे हैं, और पैनलिस्ट विचार रखने के बजाय अभिनय करने लगे हैं। बहस का स्तर ऐसा हो गया है कि कभी-कभी लगता है, अगर आवाज़ बंद कर दी जाए तो लगेगा कि यह किसी मछली बाज़ार का दृश्य है। सोशल मीडिया ने इस स्थायी चुनावी मोड़ को घर-घर पहुँचा दिया है।

रहे। आखिर एक दिन किसी जिज्ञासु ने प्रतिस्पर्धी से पूछ लिया कि तुम इतना सस्ता धी कहां से लाकर बेचोगे? उसने कहा कि मुझे तो धी बेचना ही नहीं है! उन्हें तो केवल वादों का माकेट खराब करना है। वादों के बाजार में भरसक मचानी है, सो वे बखूबी मचाते रहते हैं। और बात केवल वादों तक ही सीमित नहीं रहती है। यही खेल सरकार बनाने की घोषणाओं के मामले में भी चलता रहता है। एक पक्ष अगर सरकार बनाने की पक्की घोषणा करता है तो दूसरा पक्ष सरकार को गिराने की इतनी ही मजबूत घोषणा करता पाता जाता है। और ये सब मिलकर मीडिया को उसकी रोज की खुराक प्रदान करते हैं। हर घटना एक ब्रेकिंग न्यूज है, हर निर्णय एक षडयंत्र, और हर बयान एक ऐतिहासिक भूल। संसद और विधानसभाएँ अब कम्बोवेश टीवी स्टूडियो का विस्तार लगने लगी हैं-जहाँ बहस कम, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा सुनाई देता है। यह कहना भी कठिन हो गया है कि विधायिका और मीडिया रूप में से कौन किसका अनुकरण करता है!

असल में मीडिया ने इस पूरे परिदृश्य को एक नया आयाम दे दिया है। खबर अब सूचना नहीं, कंटेंट है-और कंटेंट वही अच्छा है, जो ज्यादा बिके। एंकर अब प्रश्न पूछने के बजाय निर्णय सुनाने लगे हैं, और पैनलिस्ट विचार रखने के बजाय अभिनय करने लगे हैं। बहस का स्तर ऐसा हो गया है कि कभी-कभी लगता है, अगर आवाज़ बंद कर दी जाए तो लगेगा कि यह किसी मछली बाज़ार का दृश्य है। सोशल मीडिया ने इस स्थायी चुनावी मोड़ को घर-घर पहुँचा दिया है। और हर नागरिक के हाथ में एक छोटा-सा चुनावी मंच है, जहाँ वह दिन में तीन बार सरकार बनाता और पांच बार गिराता है। आईटी सेल और ट्रोल्सआर्मी ने इस प्रक्रिया को इतना व्यवस्थित कर दिया है कि अब राय भी ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में आ गई है।

इसका असर प्रशासन पर भी कम दिलचस्प और दारुण नहीं है। अधिकारी अब फाहलों के साथ-साथ फीडबैक भी पढ़ते हैं-यह निर्णय जनता को कितना पसंद आएगा, और उससे भी अधिक, यह सोशल मीडिया पर कितना टूट करेगा। कठिन निर्णयों का हाल वही है जो कड़वी दवा का होता है-सब जानते हैं कि जरूरी है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता। 2025-26 के दौरान जिस तरह घोषणाओं की बाढ़ आई है-मुफ्त सेवार्थ, भत्ते, नई योजनाएँ-उसे देखकर लगता है कि सरकारें अब शासन नहीं, सम्ब्रिंक्षान मॉडल पर चल रही हैं। हर योजना के साथ एक अनकहा संदेश जुड़ा होता है-हमारी सेवा जारी रखने के लिए आलीक़िस्त वोट के रूप में जमा करें।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस निरंतर चुनावी उत्सव का अंत कहीं है। क्या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव रह जाएगा, और शासन एक साइड एक्टिविटी बनकर रह जाएगा? क्या हम नागरिक कम और स्थायी मतदाता अधिक हो गए हैं? लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं होती-वह उन दिनों में होती है, जब कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन भारत में अब ऐसे दिन ढूँढना वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने का शांतिपूर्ण समाचार-कागज़ों में पढ़ा जाता है, जमीन पर कम दिखता है।

शायद हमें अब अपने लोकतंत्र की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर यही चलता रहा, तो आने वाले समय में इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा-भारत एक ऐसा लोकतंत्र था, जहाँ चुनाव कभी खत्म नहीं होते थे।। और शासन कभी शुरू नहीं होता था।

-अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

राजस्थान के दैनिक हिन्दी अखबारों में हम खबरें कहाँ ढूँढें ?



प्रो. वीर बहादुर सिंह

पिछले लगभग दो दशकों से दैनिक अखबारों में प्रातः खबरें पढ़ने की पाठकों की मनोवृत्ति को लगातार विकर्षित कर कुठित किया जा रहा है। दैनिक अखबार महत्वपूर्ण खबरों के लिए सदैव से ही आमजन पाठकों के लिए एक सुलभ प्राप्त स्रोत रहा है। और अखबार का सखलान एक नोबल प्रोफेशन। आज़ादी के संघर्ष में देश के कतिपय नेता अखबारों से सम्बन्ध रहे हैं। कश्मीर का विख्यात कुंजूर परिवार से अखबार निकालता था, पंडित नेहरू ने भी एक अखबार की नींव डाली थी। अटल जी भी एक अखबार में एडिटिंग का काम करते थे और यहाँ तक कि देश की जनता के प्रेजिडेंट डॉ. कलाम साहब का तो फेरलू पेशा ही था वे खुद अखबार बचे थे। इस प्रकार कुल मिलाकर अखबार निकालना और बेचना एक महत्वपूर्ण और उच्च कुलीन पेशा रहा है। अखबार का पाठक अनेक कठिनाइयों होते हुए भी प्रातः सबसे पहले अखबार की खोज करता है कि

अखबार आया अथवा नहीं। लम्बे समय से दैनिक समाचार पत्र भारतीय जनता की दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। मुझे याद है जब मैं अपने गाँव के घर पर डाक से आया अखबार 'देशदूत' देखा करता था, पढ़ना तो तब आता नहीं था परन्तु मेरे दो बड़े भाई शिक्षित थे और अंग्रेजी भी पढ़-लिख लेते थे। देशदूत अखबार यह तो पता नहीं दैनिक था अथवा पाक्षिक, और यह भी अब याद नहीं कि भाषा उसकी हिंदी होती या अंग्रेजी? इतना याद है कि अखबार सीपिया रंग में छपा होता और उसमें चित्र भी सीपिया रंग के ही होते। चित्रों में उड़ते हुए और आसमान से गिरते हवाई जहाज और यूनिफार्म पहने फौजी दिखाई पड़ें। संभवतः यह समय दूसरे विश्व युद्ध और तत्काल उसके बाद का रहा होगा। मेरे भाई अखबार पढ़कर पिता जी को खबरें मौखिक बता देते।

मेरा तात्पर्य इस प्रकरण को यहाँ देने का यह है कि उस काल में देश के दूरदराज के क्षेत्रों में खबरों के लिए एक अखबार ही सबकुछ था। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन आदि कोई संचार व्यवस्था शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थीं। जिले के कतिपय प्रधान डाकघरों में आमत विद्यार्थियों में टेलीग्राम सुविधा तो सुलभ हो जाती थी।

हाँ, कभी कभार कहीं से एक पत्र का अखबार कोई छाप देता और कम संख्या में उसे कतिपय के पास पहुँचा भी दिया जाता। आजकल की युवा पीढ़ी क्या ऐसे दृश्य को मनाकर कर सकती है? जब चौबीस घंटे मोबाइल साध ही रहता हो। तात्पर्य यह है कि जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति आज़ादी के बाद शिक्षा की उन्नति से सबल हुई और इसमें दैनिक अथवा पाक्षिक अखबार की भूमिका सर्वोपरि रही।

अपने कॉलेज शिक्षा के काल का एक वृत्तांत भी यादगार बन गया। मैं छात्रावास में रहता था उसकी एक विंग में एक वार्डन भी रहते थे। हर सुबह जागने पर वे खाट पर से ही बिना आँखें खोले फर्श पर हाथ घुमाकर अखबार टटोलते। ऐसा वे नित्य करते। उनकी इस आदत से यह निकर्ष निकलता है कि जागते ही व्यक्ति विगत बीते चौबीस घंटे में क्या क्या घटित हुआ और कहाँ? इसकी जानकारी के लिए उत्सुक रहता। इस तरह की तीव्र उत्कंठा के होते आज यदि हमें 20-30 पत्रों के अखबार में खबरें ढूँढनी पड़ें तो आप क्या कहेंगे ?

वर्तमान में राजस्थान में अच्छी संख्या में हिंदी दैनिक अखबार छपते हैं। इनमें पत्रों की संख्या भी काफी संतोषजनक है फिर भी मुख्य दैनिक खबरों का अभाव अथवा सारांशित रूप में ही मिलती हैं और अनेक महत्वपूर्ण खबरें नदारद मिलेंगी। वहीं विकर्षित विज्ञापनों की भरमार, और वे भी पूरे दो पन्नों से लेकर एक पन्ना, आधा पन्ना और चौथाई पन्ना। मैंने एक तारीख को दैनिक अखबार से ऐसे लगभग बीस अति बड़े विज्ञापनों की लिस्ट बनाई तो मालूम हुआ साठ प्रतिशत से भी अधिक अखबारों का विज्ञापन में ले रहा है। मैं विज्ञापनों का विरोधी नहीं। लेकिन विचार शक्ति का यही उपयोग करते हुए उनका स्थान और क्षेत्र नियत हो तो अति उत्तम। मैं उस अखबार और विज्ञापन संस्था /संस्थानों का नाम भी नहीं

लिखना चाहता क्योंकि कम्पोजे सभो हिंदी दैनिक अखबारों की स्थिति समान ही है। परन्तु यह जरूर सलाह देता हूँ कि विज्ञापन अपेक्षाकृत छोटे बनें और सन्देश देने में सफल हों। कुछ अखबार वालों से मेरी जानपहचान भी है। एक बार मैंने एक पत्रिका कि इतने विशाल विज्ञापन देने का क्या महत्व है? कुछ नहीं बता सके, इतना जरूर कहा कि ऊपर का एक पत्र का विज्ञापन अखबार की शीथ होता है। मैं अभी तक उस शीथ का अर्थ नहीं समझ पाया। हाँ, कुछेक ने कहा- इस शीथ का उपयोग वे कार के शीशे साफ करने में करते हैं। एक अन्य ने कहा प्रातः काम पर जाते समय अखबार के ऐसे विज्ञापनों से अटे पत्रों से जुते साफ करते हैं। पाठकों को मेरा यह कथन अजुबा नहीं लगना चाहिए। बुद्धिजीवी पाठक प्रदेश के हिंदी दैनिक अखबारों के बारे में ऐसी ही राय रखते हैं भले ही वे इसे किसी से सीधे न कहें।

सम्बंधित अखबारों के मालिक यदि उचित समझें तो इस बावत एक छोटा सर्वेक्षण भी करा सकते हैं। काफी समय पहले सिनेमा घरों पर ऐसे विशाल विज्ञापनों के बोर्ड लगाते थे आज वो भी नदारद हो चुके हैं। उन्होंने अपने को क्यों बदला विज्ञापन से उन्हें क्या हानि होने लगी थी? अब केवल बहुत ही संक्षिप्त में प्रिंट मीडिया में विभिन्न सिनेमा घरों में चल रही फिल्म की सूचना यदाकदा दिख जाती है। फिर विशालकाय और भीमकाय विज्ञापन देने वाले संस्थान समय और तकनीकी के साथ मेल क्यों नहीं बिठाते ?

वर्तमान में विशाल अखबारी विज्ञापन मुख्यतः शिक्षण संस्थानों, मोटर वाइक, स्कूटर, कारों फिर शिक्षा और शिक्षण पत्रों, फिर आभूषणों और फिर खेल आदि पर होते हैं शेष विज्ञापन, विवाह, प्रॉपर्टी, हाउस लोन और रेंट व अन्य दीगर मसलों पर होते हैं। विज्ञापनों को गिनना/गिनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। क्या विज्ञापन के लिए अलग से कोई अखबार, मैगज़ीन प्रशिष्ट छापी जा सकती है? और क्या विभिन्न आयामों/विषयों पर पाठकों से विचार आमंत्रित कर उन्हें यथा स्थान अखबार में छापा जा सकता है ?

इस लेख के पाठक यह नहीं समझें कि लेख बिना अनुभव बटोरें केवल शोक के लिए लिख दिया ऐसा नहीं सोचें यदि कोई अखबारों संस्थान मेरे से इस विषय पर संवाद का इच्छुक हो तो उनका स्वागत कर उचित मशविरा ही दूँगा जो एक अध्यापक क्लृप्त मेरा कर्तव्य रहा है।

मैं यह मानता हूँ आज के युग में अखबार चलाना दुष्कर है फिर भी संतोष यह है कि अभी भी प्रदेश में हिंदी अखबारों का संकुलेशन दस लाख अथवा उससे ऊपर बना हुआ है। ये रहना चाहिए क्योंकि दैनिक अखबार प्रत्येक की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तो क्यों नहीं हम पाठकागण, चिंतक और अखबारों के मालिक मिलकर दैनिक पत्रों को कहीं अधिक उपयोगी बनाने और विकर्षण विरोधी अनुभूति युक्त करने का प्रयास करें। मैं नहीं चाहता रेडियो, ट्रांजिस्टर, सिनेमा की भाँती अब अखबार भी उस स्थिति को प्राप्त हो।

-प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

लोकतंत्र की कड़वी हकीकत: शिक्षा और शिक्षक की उपेक्षा



प्रो. अशोक कुमार

भारत, जिसने सदियों तक विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई, जहाँ तक्षिला और नालंदा जैसे केंद्र ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे, आज उसी भूमि पर शिक्षा चुनावी रैलियों के शोर में कहीं खो गई है। लोकतंत्र में सत्ता का केंद्र जनता होती है, लेकिन यदि जनता की नींव (शिक्षा) ही राजनीति के हाशिये पर हो, तो उस लोकतंत्र की मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

1. तात्कालिक लाभ बनाम दूरगामी निवेश
राजनीति अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के सिद्धांत पर चलती है। आधुनिक लोकतंत्र चुनावी चक्र (5 वर्ष) में कैद हो गया है।

दिनभर हिरणकश्यप करेगा नगर भ्रमण

भीलवाड़ा। श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर भीलवाड़ा में पिछले लगभग 100 वर्षों से श्री नृसिंह जयंती बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाई जाती है। मन्दिर के दृष्टी ओमप्रकाश अटाल ने बताया कि मन्दिर में इस बार भी 30 अप्रैल शुक्रवार को श्री नृसिंह जयंती का शुभारंभ सुबह भगवान के पंचामृत अभिषेक से होगा। इसके बाद विशेष रूप से तैयार कर्वाई गई पोशाक से भगवान का नृसिंह रूप में भव्य श्रृंगार होगा। दिनभर हिरणकश्यप रूप में कलाकार राम रतन वैष्णव नगर भ्रमण करेंगे, भक्त प्रहलाद का किरदार बाल कलाकार प्रकाश पारीक निभायेंगे। शाम को मंत्रोच्चार से नृसिंह भगवान का स्वरूप पुजारी विष्णुप्रकाश धारण करेंगे।

सड़कों का जाल और मुफ्त उपहार: जब एक नेता सड़क बनवाता है या बिजली-पानी मुफ्त देता है, तो उसका प्रभाव भौतिक रूप से तुरंत दिखता है। मतदाता को लगता है कि 'काम हुआ है'।

शिक्षा का धैर्य: शिक्षा में आज किया गया सुधार 25 साल बाद एक सभ्य और कुशल नागरिक के रूप में सामने आता है। कोई भी राजनीतिक दल उस फल को प्रतीक्षा नहीं करना चाहता जिसे काटने का अवसर शायद उनकी आगली पीढ़ी को मिले या विपक्षी दल को। यही कारण है कि शिक्षा पॉलिसी का हिस्सा तो है, लेकिन पॉलिटिक्स का नहीं।

2. संगठित वोट बैंक का अभाव
लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसान, धार्मिक समूह और जातिगत संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकारी कोट्टरों पर ला देते हैं क्योंकि वे एक वोट बैंक हैं। बिखरा हुआ शिक्षक वर्ग: शिक्षक समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, लेकिन वे वैचारिक रूप से इतने पॉलिजिज हैं कि कभी एक दबाव समूह नहीं बन पाए। राजनीतिक उदासीनता: राजनेताओं को पता है कि स्कूल की

जर्जर दीवारें या शिक्षकों की कमी उन्हें चुनाव नहीं हरवा सकती, क्योंकि आम जनता इन मुद्दों पर वोट नहीं देती। जब तक शिक्षा चुनावी हार-जीत का पैमाना नहीं बनेगी, तब तक यह नेताओं के एजेंडे में अंतिम स्थान पर ही रहेगी।

3. शिक्षा का व्यवसायीकरण: एक अंतर्विरोध
शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण ने एक अभाव स्थिति पैदा कर दी है। हितों का टकराव: देश के कई बड़े निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के तार सीधे तौर पर सत्ताधारियों से जुड़े हैं। यदि सरकारी स्कूल और कॉलेज विश्वस्तरीय बन जाएं, तो इन मंहंगे निजी संस्थानों की दुकानें बंद हो जाएंगीं।

4. सामाजिक चेतना की कमी
एक समाज के रूप में हम भी उतने ही दोगे। जनता की प्राथमिकताएं: चुनाव के समय हम जाति, धर्म, मंदिर-मस्जिद या मुफ्त मिलने वाली

सुविधाओं पर चर्चा करते हैं। क्या कभी किसी मोहल्ले ने यह कहकर चुनाव का बहिष्कार किया कि उनके यहाँ कोई स्कूल नहीं लाइब्रेरी नहीं है या प्रयोगशाला में उपकरण नहीं है?

मौन मतदाता: जब समाज ही शिक्षा को एक बुनियादी चुनावी मांग नहीं मानता, तो राजनेता उसे प्राथमिकता क्यों देंगे? नेताओं का व्यवहार समाज की मांग का ही प्रतिबिंब होता है।

5. शिक्षक की गरिमा और गैर-शैक्षणिक कार्य
शिक्षक, जिसे समाज का मार्गदर्शक माना चाहिए था, उसे आज एक बहुउद्देशीय सरकारी कर्मचारी बना दिया गया है। प्रशासनिक बोझ: जनगणना से लेकर पशु गणना और चुनावी दृष्टि तक, शिक्षकों को हर उस काम में लगा दिया जाता है जिसका शिक्षण से कोई संबंध नहीं है।

मानसिकता का पतन: जब सरकार खुद शिक्षक का उपयोग कर्त्तव्य की तरह करती है, तो समाज की नजरों में उनकी गुरु वाली छवि धूमिल हो जाती है। शिक्षक अब राष्ट्र निर्माता नहीं, बल्कि एक डेटा एंटी ऑपरेशन बनकर रह गए हैं। उनकी गरिमा का ह्रास ही शिक्षा व्यवस्था के पतन का सबसे बड़ा

कारण है। निष्कर्ष और समाधान का मार्ग शिक्षा के प्रति उदासीनता संसाधनों की कमी से ज्यादा दृष्टिकोण की कमी का परिणाम है। हमें शिक्षा को खर्च समझना बंद करना होगा। यह राष्ट्र की मानव पूंजी में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं, राजनीति का शिक्षाकरण: समय आ गया है कि शिक्षा को संविधान की गरिमा के साथ जोड़कर इसे राजनीति से ऊपर रखा जाए। शिक्षक की स्वायत्तता: शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर केवल शिक्षण और शोध तक सीमित रखना अनिवार्य है। जब तक आम नागरिक अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक लोकतंत्र की यह कड़वी हकीकत नहीं बदलेगी।

अंततः, यदि भारत को पुनः विश्व गुरु के आसन पर विराजमान होना है, तो हमें अपने गुरुओं की राजनीति के हाशिये से उठाकर राष्ट्र के केंद्र में स्थापित करना ही होगा। शिक्षा का सशक्तिकरण ही वास्तविक लोकतंत्र की विजय है।

-प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की पहल

अजमेर,(नि.सं।) महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के लिए तैयार रोस्टर रिजिस्टर को सार्वजनिक कर दिया है। कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर रोस्टर रिजिस्टर अपलोड किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों को पारदर्शिता के साथ जानकारी मिल सके। कुलसचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को कर्मचारी को रोस्टर रिजिस्टर में कोई आपत्ति है तो वह तीन दिनों के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।



राशिफल

सोमवार 27 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत् 2083, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:19 तक, ध्रुव योग रात्रि 9:36 तक, वणिज करण प्रातः 6:11 तक, चन्द्रमा रात्रि 3:36 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरु-मिथुन, शुक-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

भद्रा प्रातः 6:11 से सायं 6:16 तक रहेगी। आज मोहिनी एकादशी व्रत, श्री हित हरिविष महाप्रभु जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:33 तक, शुभ 9:10 से 10:47 तक, राहु 2:02 से 3:39 तक, लाभ-अमृत 3:39 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 7:30 से 9:00 तक सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 6:53

मेघ
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आज विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है।

वृष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटकलें हट कर्य बनें लगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनें लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्य में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कुंभ
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में पेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज समय अर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटकलें हट कर्य बनें लगे। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।